in Cantonment areas that were then unoccupied, and hence had nothing to do with buildings and structures in existence at that time;

(c) whether the Clause 7 of the said order provides that houses in a Military Cantonment, not being the property of persons belonging to the army can be requisitioned or held for use by Military personnel only at the option of the owners; and

(d) if so, the properties in Cantonment areas which were not owned by Government?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) Presumably the reference is to the General Order by the Commander-in-Chief dated 16th September, 1833. This order was made applicable to specified Cantonments and provided *inter alia*:

"In future, when any house or piece of ground within the cantonments above-mentioned may be sold or transferred, the person who makes the transfer will report the circumstances for the Officer Commanding's information and for entry in the register."

(b) and (c). A copy of Order No. 179 of 1836 has been placed on the Table of the House on 7th August, 1968 in pursuance of Unstarred Question No. 3059.

(d) The General Land Register maintained for each Cantonment in accordance with law records *inter alia* the particulars of each land, the holder of each land and the nature of the holder's rights.

**Dehiring of Properties in Cantonment Areas**

4260. SHRI K. M. MADHUKAR:
SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:
SHRI YOGENDRA SHARMA:
SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Circular has recently been issued by his Ministry regarding the dehiring of properties in Cantonment areas in which the Director of Military Lands and Cantonment has been asked not to physically release the buildings built on so-called Old Grant Sites, hired for use by the Army, on the owners requests for such dehiring unless the owner makes a declaration in writing on a stamped paper to the effect that the land concerned is held by the owner as an old grant lease under the Governor General's order No. 179 of 1836;

(b) if so, whether such an instruction does not amount to a direction to officers to defy the terms of agreement entered into with the owners of the hired buildings; and

(c) whether the above circular does not amount to an attempt to deprive citizens of their constitutional right to property?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) Yes, Sir. The declaration providing *inter alia* as mentioned, is required, to be obtained only from the applicants who hold the property on the terms mentioned.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

**विदेशों से ट्रैक्टरों का उपहार**

4261. **श्री निहाल सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपहार ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए ट्रैक्टरों के राज्यों में वितरण करने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनमें से कितने ट्रैक्टर भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है। सीमाशुल्क निकासी परमिट उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो सार्वजनिक सूचना 234/68 दिनांक 24-10-68 में दी गई शर्तें पूरी करते है चाहे आवेदक भूतपूर्व सैनिक हो अथवा न हो।

**American firm of Consultants Engaged for Ordnance Factories**

4262. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an American firm of consultants has been retained by Government to look into the state of our Ordnance Factories;

(b) if so, the name of the firm and the terms and conditions under which the firm has been engaged;

(c) the circumstances under which this firm was engaged; and

(d) the guarantees which Government have that the firm will not reveal our defence secrets to interested parties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

**पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान तथा चीन द्वारा बनाई गई सड़कें**

4263. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह:** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय क्षेत्र को असुरक्षित करने के अभिप्राय से पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तानी तथा चीनी सरकारों ने कितनी लम्बी सड़कें बनवाई हैं तथा उन सड़कों के क्या नाम हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) सदन को विदित है कि 1957 में चीन ने भारतीय प्रदेश में अकसाई चिन होते हुए लगभग 170 किलोमीटर लम्बी एक सड़क बनाई थी। तब से चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सड़क व्यवस्था को काफी सुधारा है। पाकिस्तान ने गिलगित को पाक अधिकृत काश्मीर में स्कारदू से जोड़ने वाली 240 किलोमीटर लम्बी एक सड़क बनाई जिसे उन्होंने सितम्बर, 1968 में यातायात के लिये खोला। काश्मीर-सीक्यांग सीमा पर स्थित मितांका और सुजराव दर्रों के रास्ते होते हुए गिलगित को सीक्यांग से मिलाने वाली सड़क के सम्बन्ध में सदन को 24 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर में जानकारी दी गई थी, और विदेश मंत्री ने 22 जुलाई, 1969 को एक वक्तव्य दिया था। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत काश्मीर में कुछ और छोटी मोटी सड़कें भी बना लीं हैं।

(ख) सरकार ने विरोध पत्र भेजा है और अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में इन सब बातों को ध्यान में रखा है।

**हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे**

4264. **श्री शशिभूषण :**
**श्री हुचे गोडा :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री श्रीनिवास मिश्र :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा रूस हिन्द महासागर में पृथक